लेटर्स पेटेंट अपील

न्यायमूर्ति एडी कोशल और सुरिंदर सिंह के समक्ष

मदन मोहन गोयल, अपीलार्थी।

बनाम

हरियाणा राज्य, ... प्रतिवादी।

1974 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 673

9 अगस्त, 1977 को लिया गया फैसला

पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम **1952** - नियम **9** - ***परिवीक्षा अवधि के लिए प्रदान किए गए विज्ञापन के जवाब में किसी पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति - नियुक्ति पत्र विज्ञापन का कोई संदर्भ नहीं देता है और सेवा के नियम और शर्तों को निर्धारित करते हुए ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं करता है - ऐसा व्यक्ति - चाहे वह नियुक्ति पत्र में शर्तों द्वारा शासित हो।***

आयोजित:

जहां परिवीक्षा अवधि के लिए प्रदान किए गए विज्ञापन की सामग्री नियुक्ति पत्र का हिस्सा नहीं है और किसी कर्मचारी की सेवा के नियम और शर्तें विज्ञापन से स्वतंत्र रूप से और ऐसी किसी अवधि के लिए प्रावधान किए बिना नियुक्ति पत्र में व्यापक रूप से निर्धारित की गई हैं , कर्मचारी को परिवीक्षा पर नहीं कहा जाएगा और नियुक्ति पत्र में उल्लिखित नियमों और

शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा। यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को उसमें उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में समाप्त कर दिया जाता है, तो समाप्ति अवैध होगी।

(पैरा 4)।

माननीय न्यायमूर्ति बी आर तुली द्वारा सिविल रिट याचिका सं **2007** में ***दिए गए*** दिनांक 23 ***अक्तूबर,*** **1974** के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील। **1974** ***का*** **1722** (***मदन मोहन गोयल*** **बनाम** ***हरियाणा राज्य***)।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **151** के तहत आवेदन में ***अनुरोध किया गया है कि अपीलकर्ता को दस्तावेजों*** (***अनुबंध पी*** **-41**, 9 ***फरवरी,*** **1977** के आदेश जो ***सात कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करता है और अपीलकर्ता की अनदेखी करता है) को अनुलग्नक 43 के रूप में प्रस्तुत*** करने की अनुमति दी जाती है ।

अपीलकर्ता की ओर से वकील जी. सी. गर्ग के साथ कुलदीप सिंह।

प्रतिवादी की ओर से ए.जी.(एचवाई) के वकील आई. एस. सैनी।

निर्णय

न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल, :

(1) वर्ष 1971 में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन सं 2008 के माध्यम से आर.जी. 313/69 (इसके बाद विज्ञापन के रूप में संदर्भित), ने हरियाणा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में मुख्य विद्युत निरीक्षक के अस्थायी पद पर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन के पैरा 4 और 5 में कहा गया है -

"4. पद अस्थायी है लेकिन जारी रहने की संभावना है। यह कक्षा 1 से संबंधित है। यह पेंशन योग्य है। पद का पदधारी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता लेने के लिए पात्र होगा।

5. प्रत्यक्ष भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष और पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष है। सिविल सेवा नियमों के अनुसार नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

(2) याचिकाकर्ता, जो उस समय हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में एक कार्यकारी अभियंता के रूप में सेवारत था, ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे उसी के लिए चुना गया था और 19 नवंबर, 1971 (इसके बाद 'नियुक्ति पत्र' कहा जाता है) के एक पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जिसमें विज्ञापन या इसकी किसी भी सामग्री का कोई संदर्भ नहीं था। दूसरी ओर, उन नियमों और शर्तों का विवरण दिया जिन पर नियुक्ति की जा रही थी। नियुक्ति पत्र के पैराग्राफ 1 में पद का कार्यकाल इस प्रकार वर्णित किया गया था:

1. *पद की अवधि:*

(i) नियुक्ति अस्थायी होगी, लेकिन जारी रहने की संभावना है।

(ii) यह सेवा सरकार द्वारा आपको/आपको सरकार को लिखित में एक माह की सूचना दिए जाने पर टर्मिनेबल होगी, यदि सरकार आपकी सेवा समाप्त करना चाहती है/आप बिना किसी सूचना के सेवा छोड़ना चाहते हैं, तो सरकार/आपको आपको/सरकार को एक महीने के नोटिस के बदले आपके एक महीने के परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, या उस अवधि के लिए आपकी परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करना होगा जिसके द्वारा नोटिस एक महीने से कम हो जाता है। कदाचार, अक्षमता, उपेक्षा या कर्तव्य की विफलता के मामले में, आपको मामले में प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद सेवा समाप्त हो जाएगी।

(3) याचिकाकर्ता ने नियुक्ति पत्र के तहत मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। 19 अप्रैल, 1972 के एक आदेश द्वारा, हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्य विद्युत

निरीक्षक के अस्थायी पद को स्थायी में बदल दिया। हालांकि, उस पद के संबंध में याचिकाकर्ता के कार्यकाल में किसी भी बदलाव के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया। पद पर काम करते हुए, याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थता के लिए संदर्भ प्राप्त हुए। उन्होंने फीस के भुगतान के खिलाफ फैसला किया, जिस पर सरकार की ओर से अपवाद लिया गया था, जिसने अपना स्पष्टीकरण मांगा था जो 18 दिसंबर, 1972 को एक ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अस्वीकार्य पाया गया था। 5 मार्च, 1973 को सरकार ने उन्हें सूचित किया कि परिवीक्षा पर व्यतीत अवधि के दौरान उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा था और इसलिए उन्हें उनके मूल विभाग अर्थात् हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड को वापस भेज दिया गया जिसमें उनका ग्रहणाधिकार था। सरकार की इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत कार्यवाही में चुनौती दी गई थी, जो हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता द्वारा यह बयान दिए जाने के बाद निरर्थक के रूप में विफल रही कि 5 मार्च, 1973 के आदेश को वापस लिया जा रहा है। बाद में, सरकार ने याचिकाकर्ता पर कदाचार का आरोप लगाया, जिसमें मध्यस्थता कार्य से संबंधित फीस की स्वीकृति शामिल थी और उसे पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1952 के नियम 9 के तहत कारण बताने के लिए कहा कि मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में उनकी सेवाओं को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसे फिर से असंतोषजनक पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई, 1974 के एक आदेश के माध्यम से उनकी सेवाओं को दूसरी बार समाप्त कर दिया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में चुनौती दी। उनकी याचिका को तुली, जे द्वारा 23 अक्टूबर, 1974 को एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिस पर लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत दायर इस अपील में हमला किया गया है। तुली, जे. ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना फीस के भुगतान के खिलाफ मध्यस्थता कार्य करने में संबंधित

नियमों का उल्लंघन किया था और इसलिए, सरकार ने याचिकाकर्ता को उसके मूल विभाग में इस आधार पर वापस करना उचित था कि उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया था।

(4) हमारे समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जोर दिया गया मुख्य बिंदु यह है कि विज्ञापन की सामग्री आवेदन पत्र का हिस्सा नहीं थी, कि सेवा के नियम और शर्तें जिनके द्वारा याचिकाकर्ता को शासित किया गया था, विज्ञापन से स्वतंत्र रूप से नियुक्ति पत्र में व्यापक रूप से निर्धारित किए गए थे, कि वे परिवीक्षा की किसी भी अवधि की परिकल्पना नहीं करते थे जिससे याचिकाकर्ता को गुजरना पड़ा और यह कि, इसलिए, उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए केवल सरकार द्वारा उन्हें एक महीने का नोटिस दिया गया था जो निश्चित रूप से नहीं दिया गया था। पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हम तर्क को अपवाद नहीं पाते हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है, नियुक्ति पत्र में विज्ञापन का कोई संदर्भ नहीं था। इसने परिवीक्षा की किसी भी अवधि का विज्ञापन नहीं किया जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया था। दूसरी ओर, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को "सेवा के निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर" मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद की पेशकश की जा रही थी। यदि नए पद पर याचिकाकर्ता के लिए परिवीक्षा की अवधि की परिकल्पना की गई होती, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि नियुक्ति पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया होता जैसे कि विज्ञापन में दिखाई देने वाले वेतनमान जैसी सेवा की अन्य शर्तों को नियुक्ति पत्र में दोहराया गया था। हमारी राय में, नियुक्ति पत्र में याचिकाकर्ता की सेवा के नियमों और शर्तों का एक व्यापक विवरण था और, मामले की परिस्थितियों में, विज्ञापन को इसका एक हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में हम यह भी नोट कर सकते हैं कि दोनों पक्षों को एक महीने का नोटिस देना सामान्य रूप से एक शर्त होगी जो नियुक्त व्यक्ति द्वारा परिवीक्षा की अवधि से इनकार करेगी। यह कहना नहीं है कि परिवीक्षा की अवधि और उल्लिखित प्रकार की सूचना सह-अस्तित्व में नहीं

हो सकती है, लेकिन यदि यही इरादा है, तो इसका विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने विज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया था, ने विज्ञापन को याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया, यह तय किए बिना कि नियुक्ति पत्र इसकी सामग्री के अधीन जारी किया गया था और यही वह त्रुटि है जिसमें हमारी राय में, वह गिर गया। इस संबंध में वह मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और राज्य सरकार दोनों ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद उनके बीच हुए पत्राचार में उन्हें परिवीक्षा पर होने के रूप में संदर्भित किया था, लेकिन यह तथ्य इस सवाल के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है कि क्या याचिकाकर्ता वास्तव में परिवीक्षा पर था जो कि एक मामला है। नियुक्ति पत्र की व्याख्या, और केवल इस तरह की व्याख्या, ताकि यद्यपि पूर्ववर्ती परिस्थितियां पार्टियों के इरादे पर प्रकाश डाल सकती हैं, बाद की घटनाएं इस मुद्दे पर लागू नहीं होंगी।

(5) उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश वैध था, भले ही याचिकाकर्ता परिवीक्षा पर न हो, क्योंकि उसे कदाचार का दोषी पाया गया था और नियुक्ति पत्र के पैराग्राफ 1 के अंतिम वाक्य के अनुसार उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उस वाक्य में कहा गया है:

> कदाचार, अक्षमता, उपेक्षा या कर्तव्य की विफलता के मामले में, आपको मामले में प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद सेवा समाप्त हो जाएगी।

(6) हमें इस वाक्य की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं की समाप्ति की सजा के साथ मिलने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, वह यह था कि उसे उस कदाचार का नोटिस दिया जाना चाहिए जिसके साथ उस पर आरोप लगाया गया था, कि उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए और इस तरह के

स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना चाहिए और असंतोषजनक पाया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि सजा का उद्देश्य या तो याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए कदाचार के किसी भी आरोप की नियमित जांच को खारिज करना था या इसका मतलब ऐसी कोई बात है। यह याचिकाकर्ता को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के अवसर की परिकल्पना करता है और ऐसा अवसर एक खाली औपचारिकता होगी यदि उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्वस्त करने का मौका नहीं दिया जाता है या तो यह दिखाकर कि सरकार द्वारा उसके समर्थन में भरोसा किए गए सबूत झूठे और बेकार थे या स्वतंत्र रूप से उनका खंडन करके। ऐसा अवसर एक वास्तविक अवसर होना चाहिए ताकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा परिकल्पित के समान हो। यह वह व्याख्या है जिसे हमने वाक्य पर रखा होगा, भले ही यह अस्पष्ट हो, क्योंकि, अनुमान यह होगा कि इसका उद्देश्य कानून के अनुरूप होना था और इसका उल्लंघन नहीं करना था। वास्तव में, राज्य के विद्वान वकील यह आग्रह नहीं करते हैं कि यह उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान से अलग हो।

(7) चूंकि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र में निहित उसकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार एक महीने का नोटिस या एक महीने का वेतन नहीं दिया गया था और चूंकि उसे खुद का बचाव करने का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए आक्षेपित आदेश को अवैध माना जाना चाहिए। तदनुसार अपील सफल होती है और स्वीकार कर ली जाती है और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एच.एस.बी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा